मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक SNT/10/0008/2021/41-2 भोपाल,दिनांक 15 .09.2023

प्रति,

1. अपर मुख्यसचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्यप्रदेश शासन
   नगरीय विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ वन विभाग/ऊर्जा विभाग/लोक निर्माण विभाग/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण/खनिज संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग ।
2. कलेक्टर समस्त,
   मध्यप्रदेश ।

विषय:- भारत सरकार के Call Before you Dig (CBuD) एप के उपयोग करने के संबंध में ।

संदर्भ:- भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का पत्र क्रं- D.O. No. 3-1/2022-NBM दिनांक 23/08/2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक-D.O. No. 3-1/2022-NBM दिनांक 23/08/2023 का अवलोकन करें। CBuD ऐप लॉच के बाद से, मध्यप्रदेश राज्य में सीबीयूडी मे उत्खननकर्ताओं द्वारा केवल 219 इनक्वायरी की गई हैं जिनमें से अनाधिकृत खुदाई की संख्या 40 है, अत: आपसे अपेक्षा है कि: -

1. समस्त विभाग/नगर निगम CBuD एप का उपयोग किया जाये तथा अधीन खुदाईकर्ता/खुदाई एजेंसी को भी एप का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाये।
2. सभी विभाग उत्खनन अनुमति पत्रक पर खुदाईकर्ता/खुदाई एजेंसी के लिए अन्य शर्तों के साथ CBuD एप का उपयोग किये जाने का उल्लेख कर खुदाई के पूर्व एप का उपयोग कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त संबंध में आपके विभाग से कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। अत: कृत कार्यवाही से विभाग के राज्य नोडल अधिकारी श्री राजेन्द्र अम्बाडकर, महाप्रबंधक, एमपीएसईडीसी को Email ID- rambadkar@mpesdc.com (दूरभाष नं:0755-2579090) एवं श्री खालिद खान, वरिष्ठ सलाहकार को ई-मेल Khalid.khan@mapit.gov.in (मो. 9977700479) पर अवगत कराने का अनुरोध हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ0 क्रमांक SNT/10/0008/2021/41-2 भोपाल,दिनांक 15 .09.2023

प्रतिलिपि : -

1. अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार), भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, रूम नं. 318, संचार भवन 20, अशोकशोका रोड, नई दिल्ली- 110001 की ओर उनके पत्र पत्र क्रं- D.O. No. 3-1/2022-NBM, दिनांक 23/08/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल
3. उपमहानिदेशक, भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग,कार्यालय, अपर महानिदेशक, MPLSA, दूरसंचार भवन, डाक भवन के पास,होशंगाबाद रोड़, भोपाल

   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

04/09/2023 ER-1566584/2023/41

V. L. Kantha Rao, IAS
Additional Secretary
Tel. : +91-11-23717300
Fax : +91-11-23350495
e-mail : ast-dot@gov.in
Web. : https://dot.gov.in

C.S. MONIT
मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Monit/ 1055 /2023
दिनांक 31/08/2023
समय-सीमा 15/09/2023

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS
ROOM NO. 318, SANCHAR BHAWAN
20, ASHOKA ROAD
NEW DELHI - 110001

No. 3-1/2022-NBM/ **Dated 23rd August, 2023**

Dear Sir

As you may be aware that Hon'ble Prime Minister launched **'Call Before u Dig' (CBuD) Mobile Application** on 22nd March 2023, which facilitates prevention of damage to underground utility assets viz. Optical Fibre Cable (OFC), Electricity Cables, Water pipeline, Gas/ Petroleum pipeline, roads, etc. during digging for developmental works.

2. CBuD App also provides a unique functionality for asset owners to report **unauthorised excavation** being carried out without raising an enquiry in CBuD app. The details of such unauthorised excavations are made available in, "State Nodal login" in CBuD App and Portal, thus facilitating suitable action to be taken in such cases. In the State of Maharashtra, the Director (IT) of Directorate of Information Technology is State Nodal for CBuD, who can see such unauthorized excavations details.

3. It is observed that, since the launch of CBuD, only 219 enquiries have been raised by excavators in CBuD in Madhya Pradesh State. However, **40 unauthorised excavations** have also been reported by the asset owners in the State which is quite high. This shows that CBuD App is not regularly used by excavators and in many cases the digging is being done without the use of CBuD, which must be causing damages to existing underground assets & may be causing disruption to various services.

4. In view of this, it is requested that the State Nodal officer and the State Departments may be directed to take necessary action on the reported unauthorized excavations and a suitable protocol may be established to handle such unauthorized excavations.

With regards

Yours sincerely,

(V. L. Kantha Rao) 23/8

क्र. 784/प्र.स./वि.प्रौ.
दि. 1-9-23

1137/ACS IT/23
4/9/23

PS (Science & Tech)

DS (AS)

Shri Iqbal Singh Bains, IAS
Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh
MP Mantralaya, Vallabh Bhavan
Bhopal-462004